सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 14 November TO 20 NOVEMBER 2025 • VOLUME 17 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"जो बदल सकता है वही आगे बढ़ सकता है।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	28°	12°
शनिवार	30 °	13°
रविवार	31°	12°
सोमवार	31°	13°
मंगलवार	32°	12°
बुधवार	30°	11°
वीरवार	27°	11°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

दोषियों को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी : अमित शाह

• **जालंधर ब्रीज.** अहमदाबाद

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में हुए कार विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस कार विस्फोट के ज़िम्मेदार सभी लोगों को कठोर सज़ा दिलाने का संकल्प ज़रूर पूरा होगा। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली कार विस्फोट के दोषियों को मिलने वाली सजा दुनिया को ये संदेश देगी कि भविष्य में कोई हमारे देश में फिर से ऐसा हमला करने के बारे में सोच भी न सके।

शाह ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शामिल हर एक दोषी को ढूंढकर कड़ी कार्रवाई की जाए. हमारी एजेंसियां इस कृत्य के पीछे की साजिश का गहराई से पता लगाएंगी, सभी संभावित एंगल पर जांच होगी. मैंने जांच एजेंसियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) को निर्देश दिया है कि इस मामले की हर एंगल से गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर एक दोषी को ढूंढा जाए, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। इस हमले के पीछे की साजिश और समर्थन तंत्र को जड़ से समाप्त किया जाएगा।

शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि सरकार किसी भी साजिश को अधूरा नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आतंकी घटना में शामिल व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाए. हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि दोषियों को उदाहरण बनाकर सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और इस लड़ाई का नेतृत्व करने में प्रधानमंत्री मोदी विश्व में सबसे आगे हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल और सागर ऑर्गेनिक प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि माणसा के सभी नागरिको के लिए मोतीभाई काका एक आदर्श हैं। मोतीभाई ने एक ऐसा आदर्श जीवन जिया जो पूरी तरह महात्मा गांधीजी के सिद्धांतो पर आधारित, प्रामाणिक और पारदर्शी रहा और अनेक लोगो के जीवन में इन सभी गुणो के प्रचार प्रसार करने वाला रहा।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द

दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास कार में धमाका हुआ था। इस मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी है। इसके पीछे का कारण यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं होना बताया गया है। वहीं, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है। यह नोटिस भेजकर यूनिवर्सिटी से सात सवालों के जवाब मांगे गए हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एनएएसी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करती है।

ईडी करेगी वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच

हरियाणा की फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी केस में अब प्रवर्तन निदेशालय यानि कि ईडी की एंट्री होगी। एजेंसी विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही अन्य जांच एजेंसियां भी टेरर फंडिंग और मनी ट्रेल के पहलुओं की पड़ताल में जुटी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी के खातों और अटैच संस्थानों की जांच से आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच पहले से एनआईए कर रही है। अब ईडी और ईओडब्ल्यू भी इस जांच में शामिल हो गई हैं। ऐसे में अब फरीदाबाद में बैठे आतंक के आकाओं पर चौतरफा शिकंजा कसा जा रहा है।

हर कश्मीरी आतंकी नहीं : सीएम उमर

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की निंदा की। उन्होंने कहा कि

'कुछ ही लोगों ने इस क्षेत्र में शांति और भाईचारे को नष्ट किया है और हर कश्मीरी को आतंकवाद से जुड़ा बताना उचित नहीं।' अब्दुल्ला बोले कि कोई भी धर्म इतनी क्रूरता से निर्दोष लोगों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता। जाँच जारी रहेगी, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए - जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ शांति और भाईचारे को नष्ट किया है।

दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी, यात्रियों को एयरपोर्ट, मेट्रो व ट्रेन के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर अपनी यात्रा की योजना बनाने का आग्रह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुँचना चाहिए, मेट्रो यात्रियों को कम से कम 20 मिनट पहले पहुँचना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों को अपनी उड़ान से कम से कम तीन घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुँचने की सलाह दी जाती है। इस परामर्श का उद्देश्य समय पर विमान में चढ़ने की सुविधा प्रदान करना तथा दिल्ली में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और हवाई अड्डे सहित प्रमुख परिवहन केन्द्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम समय में होने वाली देरी को रोकना है। यह परामर्श 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला परिसर के पास हुए घातक कार विस्फोट के बाद जारी किया गया है।

जम्मू रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा अभियान

जम्मू (जालंधर ब्रीज). यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया। यह अभियान रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, डॉग स्क्वायड और वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चलाया गया। इस सुरक्षा अभियान के तहत, जम्मू रेलवे स्टेशन और आसपास के रेलवे परिसर की गहन जाँच की गई। यात्रियों के सामान, प्लेटफार्मों और आने-जाने वाली ट्रेनों की मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वायड द्वारा चैक किया गया। प्रतीक्षालय, आरक्षण काउंटर, बुकिंग कार्यालय और पार्सल कार्यालय का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य, रेलवे स्टेशन पर सामान्य रेल यातायात सुनिश्चित हो। जिससे की यात्रियों को कोई असुविधा न पहुंचे। मंडल के अधिकारियों द्वारा स्टेशन पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को भी ड्यूटी के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई कि यात्रा के दौरान सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुए, बल्कि तुरंत सुरक्षा कर्मियों तथा रेलवे की हेल्प लाइन नंबर 139 व 182 पर सूचित करें।

डीएनए टेस्ट से पुष्टि- डॉ. उमर नबी चला रहा था विस्फोटक से भरी कार

नई दिल्ली. लाल किला विस्फोट स्थल से एकत्र किए गए नमूनों के डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई है कि डॉ. उमर नबी उस कार को चला रहा था जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में विस्फोट हुआ था। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि उमर की मां के डीएनए नमूने मंगलवार को एकत्र किए गए और जांच के लिए यहां भेजे गए। उन्होंने बताया कि विस्फोट स्थल से एकत्र अवशेषों के साथ डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया गया। एक सूत्र ने कहा, 'डीएनए के नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में उमर ही विस्फोट में इस्तेमाल कार चला रहा था।' उमर इस सप्ताह की शुरुआत में पर्दाफाश किए गए एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का एक प्रमुख सदस्य था। वह जम्मू कश्मीर में पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला था। पुलिस द्वारा प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और तीन चिकित्सकों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास एक धीमी गति से चलती कार में उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ। पुलिस ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में फैले आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद लगभग 3,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर जब्त किया।

डॉक्टर, फ़र्ज़ी पहचान पत्र व कट्टरपंथी संबंध

पुलिस का कहना है कि उमर 9 नवंबर से लापता था, जिसके एक दिन पहले फरीदाबाद के एक गोदाम से लगभग 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। माना जा रहा है कि वह धौज गाँव के पास भूमिगत हो गया था, उसने 30 अक्टूबर से पाँच फ़ोन बंद कर दिए थे और विश्वविद्यालय की ड्यूटी भी नहीं की थी। इसके बाद से व्यापक जाँच में कई अन्य लोग भी फँस गए हैं। इनमें फरीदाबाद से गिरफ़्तार की गई पूर्व व्याख्याता डॉ. शाहीन शाहिद भी शामिल हैं, जिनके बारे में जाँचकर्ताओं का मानना है कि वह जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह की पहली महिला शाखा, जमात-उल-मोमिनात की भारत इकाई की प्रमुख बनने वाली थीं।

5000 रुपये रिश्वत लेते हुए एएसआई रंगे हाथों काबू किया

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने गुरुवार को थाना कोट ईसे खां, जिला मोगा में तैनात एएसआई रघविंदर प्रसाद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसे शिकायतकर्ता, निवासी तहसील मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों के खिलाफ थाना कोट ईसे खां में एक मामला दर्ज था, जिसकी जांच एएसआई रघविंदर प्रसाद कर रहा था। जांच में मदद करने के बदले आरोपी एएसआई ने 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत प्राप्त होने पर एसएएस नगर स्थित विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में एएसआई रघविंदर प्रसाद को शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया।

350वें शहीदी दिवस के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों को सुरक्षित और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंजाब पुलिस ने संगतों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्नत निगरानी प्रणाली, बल की रणनीतिक तैनाती और 24 घंटे तालमेल के साथ एक व्यापक, बहु-स्तरीय सुरक्षा और सुविधा योजना लागू की है। यह जानकारी आज यहां स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (स्पेशल डीजीपी) कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने दी।

श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर, 2025 तक आयोजित होने वाले इन विशाल स्मृति समारोहों में देश-विदेश से भारी संख्या में संगतों के आने की उम्मीद है। स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने स्पेशल डीजीपी (सुरक्षा) सुधांशु एस. श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में एडीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) एस.पी.एस. परमार और एसएसपी रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना भी मौजूद थे। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि समारोहों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए एडीजीपी रैंक के नोडल अधिकारी की देखरेख में लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही सात आईजी/डीआईजी रैंक के अधिकारी, 22 कमांडेंट, 45 एसपीजऔर 94 डीएसपीज भी तैनात किए जाएंगे।

किसकी होगी बिहार में सत्ता, फैसला आज

पटना. क्या बिहार में नीतीश कुमार का दो दशक पुराना शासन जारी रहेगा, या राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभालने के बाद अपनी पहली बड़ी चुनावी जीत हासिल करेंगे? इसका जवाब आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही मिल जाएगा। भाजपा, जदयू और लोजपा (रामविलास) वाला राजग एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की उम्मीद कर रहा है जबकि विपक्षी दल महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल प्रमुख घटक हैं, अगली सरकार बनाने की उम्मीद कर रहा है। 2020 के बिहार चुनाव में जब नीतीश कुमार ने मामूली बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को 12,000 से कुछ अधिक वोटों की कमी खली थी। इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर हैं। दोनों चरणों में 38 जिलों के 7.4 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं ने 2,616 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए वोट डाले। बिहार में ऐतिहासिक 67.13% मतदान हुआ - जो 1951 के बाद से सबसे ज़्यादा है। फिलहाल पूरे राज्य में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बिहार में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड पांचवां कार्यकाल हासिल कर पाएंगे।

645 करोड़ रुपये के रैकेट का पर्दाफाश, मुख्य संचालक गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), दिल्ली की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली के एक सिंडिकेट की ओर से चलाए जा रहे 229 फर्जी जीएसटी-पंजीकृत फर्मों के एक नेटवर्क के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी करके लाभ उठाने और उसे पास करने के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है।

विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर, डीजीजीआई अधिकारियों ने दिल्ली भर में कई परिसरों में सुनिश्चित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और बहीखाते बरामद हुए, जिनसे पता चला कि ऐसी गैर-मौजूद कंपनियां बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति के चालान जारी करने में लगी हुई थीं। इसमें 162 मोबाइल फोन, जिनका इस्तेमाल संभवतः जीएसटी/ बैंकिंग उद्देश्यों के लिए ओटीपी पता करने में किया गया था, 44 डिजिटल हस्ताक्षर और विभिन्न फर्मों की 200 से अधिक चेकबुक शामिल थीं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि ये फर्जी संस्थाएं बिना किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति के चालान जारी करने में लगी हुई थीं, जिसके चलते लगभग 645 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी धोखाधड़ी से पारित की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

लुधियाना में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, हैंड ग्रेनेड समेत 10 गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/लुधियाना

लुधियाना पुलिस आयुक्तालय ने विदेशी हैंडलरों से जुड़े 10 मुख्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर आईएसआई समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को दी। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान कुलदीप सिंह, शेखर सिंह और अजय सिंह उर्फ अजय के रूप में हुई है, जो सभी श्री मुक्तसर साहिब के निवासी हैं। जबकि अमरीक सिंह, परमिंदर उर्फ चिड़ी, विजय, सुखजीत सिंह उर्फ सुख बराड़, सुखविंदर सिंह, करनवीर सिंह उर्फ विक्की और साजन कुमार उर्फ संजू को कूरियर और सहयोगी की भूमिका निभाने के आरोप में विभिन्न जेलों से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। पुलिस टीमों ने आरोपियों से एक 86पी चीनी हैंड ग्रेनेड, एक काली किट, और दस्तानों का एक सेट बरामद किया है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि आगे की जांच में मलेशिया-आधारित विदेशी मास्टरमाइंड – अजय उर्फ अजय मलेशिया, जस्स बहिबल और पवनदीप – की पहचान की गई है। ये सभी मलेशिया में एक साथ रहते हैं और पंजाब में अमरीक सिंह तथा परमिंदर उर्फ चिड़ी से संपर्क में थे, जो पहले उनके लिए नशीले पदार्थों की तस्करी का कार्य करते थे।

सीपी स्वपन शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान अजय (मलेशिया) के भाई विजय, जो गंगानगर जेल में एनडीपीएस अधिनियम के तहत बंद था, को भी इस मामले में सहयोगी की भूमिका निभाने के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। आगे जांच में स्थानीय नेटवर्क का भी खुलासा हुआ, जिसमें सुखजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, करणवीर सिंह और साजन उर्फ सानू शामिल हैं, जिन्होंने पंजाब में हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी में मदद की थी। सीपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (यू ए पी ए) की धाराएँ लगाई गई हैं और विदेशों में सक्रिय आरोपियों के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस (आर सी एन) जारी किए गए हैं।

अमृतसर में प्रोविज़नल स्टोर पर हुई फायरिंग के पीछे जग्गू भगवानपुरिया गैंग, दो गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर (जालंधर ब्रीज). अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने जंडियाला गुरु में जबरन वसूली की कोशिश से जुड़ी गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि, निवासी पंडोरी वडैच, और उज्जवल हंस, निवासी बटाला रोड, अमृतसर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, तीन अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने 6 नवंबर को जंडियाला गुरु स्थित एक प्रोविज़नल स्टोर के मालिक को डराने और जबरन वसूली के लिए उसकी दुकान पर गोलियां चलाई थीं।

डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े हुए हैं और वे अपने विदेशी हैंडलर केशव शिवाला के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

बटाला में जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के दो सहयोगी काबू

चंडीगढ़/बटाला (जालंधर ब्रीज). बटाला पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह से संबंधित विदेशी गैंगस्टर अमृत दालम के दो मुख्य सहयोगियों को दो विदेशी .30 कैलिबर पिस्तौलें और जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने गुरुवार को दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विजय मसीह (निवासी सतकोहा, बटाला) और मलकित सिंह (निवासी नाहरपुर खदर, बटाला) के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों आरोपियों को गैंगस्टर अमृत दालम ने टारगेट किलिंग करने का काम सौंपा था। दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकॉर्ड है और उनके खिलाफ इरादा हत्या, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संबंधों की पहचान के लिए जांच जारी है।

वीकेंड ट्रिप के लिए बेस्ट है भरतपुर नेशनल पार्क, रंग-बिरंगे पक्षियों के बीच मिलेगा सुकून

Travelling दिल्ली और आसपास के शहर में रहते हैं और भागदौड़ से दूर वीकेंड पर कहीं सुकून की तलाश में हैं तो भरतपुर नेशनल पार्क बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। बर्ड सेंक्चुरी के अलावा भरतपुर में और भी कई जगहें सैर के लिए बेस्ट हैं...

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

दिल्ली और आसपास के एरिया में रहते हैं। हर दिन 9-5 जॉब करते हैं। वीकेंड फैमिली और दोस्तों के साथ कुछ समय सुकून के बिताना चाहते हैं। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। जहां पर जंगलों के बीच आपको पक्षियों के नजारों के साथ ही जंगल वाला एकांत भी मिलेगा। जहां पर आप भरपूर समय गुजारकर खुद को फिर से फ्रेश और एनर्जेटिक बना सकते हैं। भागदौड़ भरी लाइफ से कुछ समय खुद के और फैमिली के लिए निकालना चाहते हैं तो ये जगह काफी सारी टूरिस्ट की पसंदीदा बन जाती है। जहां पर आपको शानदार नजारे देखने को मिलते हैं।

भरतपुर बर्ड सेंचुरी जाने का समय

भरतपुर बर्ड सेंचुरी का असली नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। जो कि भरतपुर जिला राजस्थान में बना हुआ है। वीकेंड ट्रिप के लिए दिल्ली के आसपास की जगहों में ये नेशनल पार्क भी टॉप पर रहता है। जहां पर आप फैमिली के साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खासतौर पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का समय बेस्ट माना जाता है। इस वक्त पर यहां लोकल बर्ड के अलावा माइग्रेटेड पक्षी भी आते हैं। जिन्हें देखने के ये समय बेस्ट होता है।

भरतपुर बर्ड सेंचुरी में देखने के लिए क्या है

भरतपुर बर्ड सेंचुरी में देखने के लिए प्रवासी पक्षियों में साइबेरियन सारस, बार हेडेड गीज, पेलिकन और पेंटेड स्टार्क आते हैं। साथ ही लोकल पक्षियों की ढेर सारी वैराइटी भी देखने को मिलती है। पक्षियों के अलावा यहां पर अजगर, मॉनिटर छिपकलियां, कुछ वाइल्ड कैट, गोल्डन सियार, जंगली सुअर, सांभर हिरण, चितल हिरण भी देखे जा सकते हैं। कई सारी कछुओं की वैराइटी भी यहां देखने को मिलती है।

भरतपुर में और भी जगहों पर करें सैर

भरतपुर में नेशनल पार्क के अलावा लोहागढ़ फोर्ट भी टूरिस्ट प्लेस है। जहां पर टूरिस्ट इस किले की शानदार डिफेंस क्वालिटी देखने आते हैं। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर, भरतपुर पैलेस और म्यूजियम भी सैर करने वाले प्लेसेज हैं। भरतपुर में बने गंगा मंदिर को टूरिस्ट इसके अनोखे इतिहास की वजह से देखने के लिए पहुंचते हैं, जो कि करीब 90 साल पुराना है। लक्ष्मण मंदिर, गवर्नमेंट म्यूजियम भी देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं।

कैसे पहुंचे भरतपुर

भरतपुर रेलवे स्टेशन सभी प्रमुख स्टेशनों से पूरी तरह से कनेक्टेड है। दिल्ली से भरतपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना सुविधाजनक हो सकता है। मात्र ढाई घंटे में आप यहां आराम से पहुंच सकते हैं। वहीं दिल्ली से बस और प्राइवेट कैब के जरिए भी भरतपुर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से भरतपुर की दूरी 236 किमी है।

PARENTING

12 से 16 साल की उम्र के बच्चों को कितनी आजादी देना सही है? जानें एक्सपर्ट की राय

12 से 16 साल की एज में बच्चों को आजादी की जरूरत तो होती है, लेकिन उसी के साथ सही गाइडेंस और सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं इस उम्र में बच्चों को कितनी फ्रीडम देना सही है।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

12 से 16 साल की उम्र बच्चों के जीवन का वो समय होता है, जब वे खुद को समझने और अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ना तो वो पूरी तरह बच्चे रहते हैं और ना ही मैच्योर होते हैं। ऐसे में वे अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि फैमिली में उनकी बात को अहमियत दी जाए। इस एज के बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी यह काफी मुश्किल वक्त होता है। क्योंकि यही वह समय होता है जब पेरेंट्स के लिए यह तय करना सबसे मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को कितनी आज़ादी दी जाए, जिससे बच्चों को फ्रीडम भी मिले और सही रास्ता भी दिखाया जा सके। पेरेंटिंग कोच कहती हैं कि 12 से 16 साल की एज में बच्चों को आजादी की जरूरत तो होती है, लेकिन उसी के साथ सही गाइडेंस और सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं उनके मुताबिक इस उम्र में बच्चों को कितनी फ्रीडम देना सही है।

फ्रीडम कोई अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का इनाम है

पेरेंटिंग कोच कहती हैं कि बच्चों को आजादी तभी देनी चाहिए जब वे उसकी जिम्मेदारी उठाना सीख जाएं। यानी फ्रीडम कोई राइट नहीं बल्कि एक रिवॉर्ड है। अगर बच्चा अपना स्कूल वर्क ईमानदारी से करता है, समय का सही उपयोग करता है और घर के बेसिक रूल्स को फॉलो करता है, तो उसे धीरे-धीरे डिसीजन मेकिंग में शामिल करना चाहिए। जब बच्चा जिम्मेदारी के साथ फ्रीडम को संभालना सीख जाता है, तो वह अपने जीवन के फैसलों में भी बेहतर सोच विकसित करता है।

बच्चों की राय सुनें, लेकिन सीमाएं तय रखें

12 से 16 साल की उम्र में बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ समझ आने लगा है। वे अपनी राय पर ज्यादा भरोसा करते हैं और पेरेंट्स की बातों को चुनौती भी देने लगते हैं। इस स्टेज पर पेरेंट्स का धैर्य बहुत मायने रखता है। कोच कहती हैं कि बच्चों की ओपिनियन को इग्नोर ना करें। उनकी बात ध्यान से सुनें, उन्हें यह महसूस कराएं कि उनकी राय की कीमत है। लेकिन साथ ही, यह भी स्पष्ट रखें कि अंतिम निर्णय अभी भी आपका होगा। इससे बच्चा सीखता है कि उसकी बात मायने रखती है, लेकिन सीमाएं भी जरूरी हैं।

सही संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है

पेरेंटिंग कोच कहती है कि 12 से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे ना तो पूरी तरह बच्चे रहते हैं और न ही पूरी तरह बड़े बनते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को सख्ती और नरमी के बीच एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। बच्चे को गाइड करें, लेकिन उसे अपनी गलतियों से सीखने का स्पेस भी दें। कोच कहती हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चों को समझदारी से फ्रीडम देंगे, तो वे आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनकर आगे बढ़ेंगे।

डिस्क्लेमर : *इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।*

आंवला कैंडी बनाने का तरीका घर में ही सीख लें, बच्चे-बड़े सब चाव से खाएंगे

सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ बालों और स्किन की देखभाल करनी है तो आंवला खाना बेस्ट ऑप्शन होता है। आंवले की चटनी, अचार, मुरब्बा तो कई बार खाया होगा। लेकिन अब घर में मार्केट जैसी आंवला कैंडी भी ..

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आंवला खाना बेस्ट ऑप्शन है। आवंले में विटामिन सी के साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। सात ही स्किन और बालों के लिए बी फायदेमंद होता है। तो अगर अब अपने बालों की ग्रोथ चाहती हैं और स्किन में निखार पाना है तो रोजाना आंवला खाएं। आप चाहें तो स्मार्ट तरीके से आंवले की कैंडी बनाकर रख लें। ये आंवला खाने का स्मार्ट तरीका है। तो नोट कर लें आंवला कैंडी घर में बनाने की रेसिपी।

आंवला कैंडी बनाने की सामग्री

- ताजे हरे आधे किलो आंवला
- धागे वाली मिश्री 100 ग्राम
- नींबू का रस
- देसी घी
- नमक स्वादानुसार

आंवला कैंडी बनाने की सामग्री

- सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह से धो लें। फिर इन्हें भाप में उबलने के लिए रख दें।
- ध्यान रहे कि इन्हें पानी में नहीं उबालना है।
- जब ये अच्छी तरह से उबल जाए तो इनके बीजे अलग कर लें और ग्राइंडर जार में पेस्ट बना लें।
- धागे वाली मिश्री को पीसकर पाउडर बना लें।
- अब किसी पैन में पिसे हुए आंवले के पेस्ट को डालकर भूनें।
- कुछ देर बाद उसमे मिश्री डालकर अच्छी तरह से चलाएं।
- जब ये मिक्स होकर एक सार हो जाए तो देसी घी एक चम्मच डाल दें। एक चम्मच नमक भी मिला दें।
- साथ ही नींबू का रस भी मिला दें। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनें। जिससे कि ये पूरी तरह से मिक्स होकर तली छोड़ दे।
- जब ये कलर बदलकर तली छोड़ दे। तो इसे किसी बटर पेपर लगे डिब्बे में पलट लें और शेप दें।
- ठंडा होने पर काट लें तो ये बिल्कुल जेली जैसी लगेंगी।
- बस अब किसी प्लेट में थोड़ा सा मिश्री पाउडर और नमक मिक्स करके रख लें।
- तैयार कैंडी को इसमे लपेटें और एयर टाइट डिब्बे में भर लें।
- बस रेडी हैं टेस्टी आंवला कैंडी, जिसे आप बच्चों को खाने को दें।

हर किसी को जानने चाहिए जीवन के 5 कड़वे सच, हमेशा खुश रहेंगे और खुलकर जीएंगे

जालंधर ब्रीज (फीचर) . हर इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी कई बार दुख, परेशानी और तनाव हमें घेर ही लेते हैं। दरअसल, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हम जीवन के कुछ बेहद सरल लेकिन गहरे सच को नजरअंदाज कर देते हैं। जो व्यक्ति इन बातों को समझ लेता है, वो छोटी-छोटी बातों में उलझता नहीं और हर हाल में खुश रहना सीख जाता है। जबकि जो इंसान इन सच्चाइयों को नजरअंदाज करके बेवजह की उम्मीद लगाए बैठा रहता है, उसे दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलता है।

हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, हर परिस्थिति वैसी बने जैसी हम चाहें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जीवन में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, जैसे-पूरी मेहनत के बाद भी फल ना मिलना, किसी दूसरे का आपके साथ बुरा व्यवहार करना या अचानक कोई मुश्किल खड़ी हो जाना। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना नामुमकिन है, तो मन को शांति मिलने लगती है। नियंत्रण की जरूरत कम हो जाती है और हम चीजों को स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही बात हमारी चिंता को घटाकर खुश रहने की राह खोलती है।

कहने को तो ये बात बेहद छोटी है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। लोग ये बात सुन तो लेते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं होते कि समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। अच्छे दिन आते हैं और चले भी जाते हैं, वैसे ही बुरे वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होते। अगर हम इन बातों को समझ लें कि हर चीज बदलने वाली है, तो हम दुख के समय टूटते नहीं और सुख के समय घमंड नहीं करते। परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानना हमें संतुलित बनाए रखता है और लाइफ के इस बैलेंस में ही सच्चा सुख छिपा हुआ है।

इंसान के दुख की सबसे बड़ी वजह है कि वह दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी और की जिंदगी को देखकर,

डिस्क्लेमर : *इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।*

सर्दियों में मूली खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे बीपी हो या डायबिटीज दोनों रहते हैं कंट्रोल

Health मूली का सेवन खासतौर पर बीपी और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं मूली का सेवन सेहत को देता है क्या गजब के फायदे।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बाजार में सफेद और लाल रंग की मूली दिखाई देने लगती है। लोग मूली के पराठे से लेकर उसका सलाद और सब्जी बनाकर खाना बेहद पसंद करते हैं। मूली ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्वों की वजह से सेहत को भी अनजाने में कई गजब के फायदे देती है।

बता दें, मूली में फाइबर, पोटैशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो बदलते मौसम में व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करके उसे जल्दी बीमार होने से बचाते हैं। मूली का सेवन खासतौर पर बीपी और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं मूली का सेवन सेहत को देता है क्या गजब के फायदे।

मजबूत पाचन तंत्र : सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच परेशान करने लगती हैं। लेकिन मूली का सेवन सलाद में करने से पाचन तंत्र अच्छा बना रहता है, जिससे पाचन संबंधित समस्याएं कंट्रोल में की जा सकती हैं।

बॉडी करें डिटॉक्सिफाई : कई बार शरीर में अलग-अलग माध्यम से कई विषैले तत्व जमा होने लगते हैं, जो समय के साथ कई बीमारियों को जन्म देने लगते हैं। जिससे बचने के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में मूली का सेवन शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। यह किडनी और लीवर को मजबूत बनाता है। जिससे त्वचा में निखार आता है।

डायबिटीज रखें कंट्रोल : मूली में ग्लिासेमिक इंडेक्स कम मात्रा में मौजूद होता है। इसका सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में मूली को जरूर शामिल करना चाहिए।

दिल की सेहत : मूली एंथोसायनिन का एक अच्छा स्रोत है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट हृदय को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, सूजन कम करता है और रक्तचाप तथा खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद करता है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे : पोटेशियम से भरपूर मूली ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम सोडियम के प्रभावों को कम करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बेहतर बनाता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

"नक्शा" : विश्वसनीय भू-अभिलेखों और नागरिक सशक्तिकरण के लिए एक नई पहल

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

जब भारत एक समावेशी और विकसित भविष्य की कल्पना करता है, तो इसका सबसे मज़बूत आधार-स्तंभ भूमि है। चाहे घर हो, खेत हो, दुकान हो या स्मार्ट सिटी का सपना हो - विकास का प्रत्येक रूप भूमि पर अवस्थित होता है। हालाँकि, सच्चाई यह है कि वर्षों से हमारे भू-अभिलेख अधूरे, भ्रामक और अक्सर विवादों में उलझे रहे हैं। परिणामस्वरूप, आम नागरिकों को संपत्ति खरीदने, ज़मीन विरासत में प्राप्त करने, ऋण प्राप्त करने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

इन दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने "नक्शा" (राष्ट्रीय शहरी निवास-स्थल भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण) कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह भारत में भूमि प्रबंधन, प्रशासन और भूमि-रिकॉर्ड रख-रखाव में बदलाव लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम एक पारदर्शी, डिजिटल और सत्यापित भू-अभिलेख प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो न केवल नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि कस्बों और शहरों के विकास को भी गति प्रदान करेगी। भारत में, भूमि पंजीकरण लंबे समय से एक जटिल व दस्तावेज-आधारित प्रक्रिया रही है। बिक्री विलेख, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, पटवारी सत्यापन और तहसील स्तर पर प्रस्तुतियाँ - ये सभी नागरिकों के लिए पूरी प्रणाली को बोझिल बना देती थीं। पुराने रजिस्टर और फाइलों में न केवल त्रुटियां मौजूद थीं, बल्कि इनमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी, जो कई विवादों का मूल कारण होता है। अस्पष्ट संपत्ति अभिलेखों की वजह से बैंकों से ऋण प्राप्त करने की संभावना कम हो गयी थी।

उत्तराधिकार या दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अक्सर वर्षों तक अदालतों में अटकी रहती थी। गलत माप, अस्पष्ट सीमाएँ और स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। यही कारण है कि लाखों भारतीयों के लिए, सुरक्षा के स्रोत के रूप में भूमि का महत्त्व कम होता गया और यह जोखिम का प्रमुख स्रोत बन गई।

डिजिटल पारदर्शिता की ओर कदम

नक्शा कार्यक्रम, सटीक और डिजिटल भू-रिकॉर्ड तैयार करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण, जीएनएसएस मानचित्रण और जीआईएस उपकरण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है। इस पहल के तहत, नागरिकों को 'योरप्रो' (शहरी संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्ड) कार्ड मिलता है, जो

"नक्शा" आपकी भूमि की डिजिटल पहचान का प्रतीक

शिवराज सिंह चौहान
(केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार)

स्वामित्व का एक डिजिटल प्रमाण है और संपत्ति के लेन-देन को आसान बनाता है। सरकार 'योरप्रो' कार्यक्रम को समर्थन दे रही है। नक्शा के साथ, लोगों को अब स्वामित्व की पुष्टि के लिए दस्तावेजों या बिचौलियों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इससे ऋण प्राप्त करने, बिक्री पूरी करने, उत्तराधिकार प्राप्त करने और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया तेज़ और अधिक पारदर्शी हो गयी है। अंततः, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है - यह नागरिक सशक्तिकरण, समानता और भू-स्वामित्व में कानूनी आश्वासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नक्शा कार्यक्रम मुख्य रूप से उन नागरिकों को लाभान्वित करता है, जो लंबे समय से अधूरे या अप्रचलित भू-दस्तावेजों पर निर्भर रहे हैं। नगरपालिकाओं और स्थानीय परिषदों के पास अब स्वच्छ, सटीक भू-स्थानिक डेटा तक पहुँच की सुविधा है, जिससे बेहतर निर्णय लेना और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। नागरिक आसानी से ऑनलाइन प्रारूप मानचित्र देख सकते हैं और आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह डिजिटल प्रणाली कराधान को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाती है, साथ ही शहरी नीति-निर्माण और अवसंरचना डिज़ाइन की सटीकता और गति में सुधार करती है। संक्षेप में, जो भू-रिकॉर्ड कभी धूल भरे रजिस्टरों में केवल हस्तलिखित प्रविष्टियों के रूप में मौजूद था, वह अब रंगीन, इंटरैक्टिव और पारदर्शी डिजिटल मानचित्रों में विकसित हो गया है। यह आधुनिक, डेटा-संचालित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नक्शा कार्यक्रम का प्रभाव व्यक्तिगत स्वामित्व और प्रशासनिक दक्षता से कहीं आगे तक फैला हुआ है और यह आपदा प्रबंधन और शहरी नीति-निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। अवस्थिति की ऊँचाई का विस्तृत डेटा प्रदान करके, यह लोगों को बाढ़-जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि चक्रवात, भूकंप या आग की स्थिति में, यह बिना किसी देरी के बचाव और राहत कार्यों को शुरू करने की सुविधा देता है। सत्यापित डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड यह भी सुनिश्चित करते हैं कि मुआवजा और सहायता सही लाभार्थियों तक शीघ्रता से पहुँचे। इससे आपदा के बाद, पूर्वस्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। इसके अलावा, नक्शा संतुलित और सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक शहरी सुदृढ़ता का समर्थन करता है।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और दिव्यांगजनों जैसे कमजोर समूहों के लिए, नक्शा सुरक्षा और सुलभता प्रदान करता है—उन्हें संपत्ति के रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने और सत्यापित करने की सुविधा देता है, किसी भी धोखाधड़ी और अतिक्रमण के जोखिम को कम करता है, और सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाए बिना आसान पहुँच सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, नक्शा केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि दुनिया भर के उन नागरिकों के लिए विश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिनकी भारत की भूमि और इसके भविष्य में हिस्सेदारी है।

विकसित भारत की आधारशिला

भारतीय इतिहास में, भूमि विवादों ने अक्सर असमानता, संघर्ष और विलंब को जन्म दिया है—लेकिन नक्शा कार्यक्रम भूमि प्रशासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बनाकर इस विरासत को बदल रहा है। स्मार्ट शहर, पीएम गति शक्ति और पीएम स्वनिधि जैसे राष्ट्रीय मिशनों के साथ एकीकरण के जरिये, नक्शा भारत के विकास-केंद्रित भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। यह न केवल स्थानीय शासन को मज़बूत करता है, बल्कि नागरिक भागीदारी, सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे अधिक निवेश और रोज़गार सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है।

आख़िरकार, भूमि सिर्फ़ एक भौतिक संपत्ति नहीं है—यह प्रत्येक भारतीय नागरिक की पहचान और विरासत है। दशकों से, यह विरासत अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आवरण से ढँकी हुई थी, लेकिन नक्शा विश्वास, पारदर्शिता और समानता का अमृत काल प्रस्तुत कर रहा है। सुरक्षित, सत्यापित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ, अब नागरिकों के पास सचमुच अपने सपनों की कुंजी है—जो भारत को एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकसित भविष्य की ओर ले जा रही है।

भारत की श्रम संहिताएं : अनौपचारिकता से समावेशन की ओर

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . जैसे विश्व भर के देश प्रतिभाओं के लिए अपने भीतर देख रहे हैं। ऐसे में भारत को भी औपचारिक, औचित्यपूर्ण और गरिमामय रोजगार पैदा कर आगे बढ़ना होगा। समूची दुनिया में आव्रजन को लेकर चिंता, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं को नया स्वरूप दे रही है। वैश्विक प्रतिभाओं का स्वागत करने वाले देश अब बदल रहे हैं, वे वैश्विक प्रतिभाओं के लिए पुल बनाने के बजाय अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभाओं की तलाश अपने अंदर ही शुरू कर दी है। भारत इस बदलती हुई दुनिया में संपन्नता के लिए सिर्फ प्रतिभाओं के निर्यात पर निर्भर नहीं रह सकता। हमें उत्पादन के साथ ही अवसरों के लिहाज से भी आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके जरिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वदेशी प्रगति के साथ ही देश में अच्छे भुगतान वाले, मानकीकृत और गरिमापूर्ण रोजगार पैदा हों।

कार्तिक नारायण
(मुख्य कार्याधिकारी, अपना जॉब्स)

मार्टिन लूथर किंग (जू॰) ने एक समय कहा था, ''मानवता को ऊपर उठाने वाले हर श्रम की गरिमा और महत्व है। इसे श्रमसाध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए।'' भारत की नई श्रम संहिताएं इस आदर्श को जमीन पर उतारने की दिशा में एक कदम हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश को बनाने, आगे ले जाने और शक्ति देने वाले लाखों लोग सिर्फ कामगार नहीं हों, बल्कि प्रगति में हिस्सेदार बनें। इन संहिताओं का लक्ष्य अनौपचारिकता को समावेशन, स्वेच्छा को आंकड़ों और असुरक्षा को सुदृश्यता से बदल कर काम की गरिमा बहाल करना है। भारत का श्रम परिवेश वर्षों से पैबंदों वाली दरी के समान रहा है। देश के 29 श्रम कानून बेशक अच्छे इरादे से लाए गए हों लेकिन सब मिल कर अस्पष्टता पैदा करते रहे थे। इसके परिणामस्वरूप अकुशलता का संतुलन दिखाई पड़ता था। कामगार में असुरक्षा थी और नियोक्ता संदेह में रहते थे। सरकार ने इन कानूनों को वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा की चार संहिताओं में पिरो देने का फैसला किया। यह कदम सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है। आधुनिकीकरण के इस अभियान में स्वीकार किया गया है कि संरक्षण और उत्पादकता को एक साथ मिलकर बढ़ना चाहिए। इस सुधार का संबंध दृश्यता से है। नियुक्तिपत्र, वेतन की पर्ची और डिजिटल रिकॉर्ड के बिना कामगार, सरकार और बाजार दोनों की ही नजरों से ओझल रहता है। औपचारीकरण इस स्थिति में बदलाव लाता है। लिखित प्रमाण वाला हर रोजगार एक ऐसा जीवन पैदा करता है जिसकी मान्यता हो। हर डिजिटल रिकॉर्ड सामाजिक सुरक्षा से लेकर बीमा और गतिशीलता तक जाने वाला पुल होता है। यह बदलाव नियोक्ताओं को भी अनिश्चितता के बजाय एक ढांचा और स्वेच्छा की जगह आंकड़े प्रदान करता है। नियुक्ति के हर संबंध का रिकॉर्ड हो तो विश्वास को एक बुनियाद मिल जाती है।

वेतन को ही लें। भारत में विभिन्न राज्यों और उद्योगों की अलग-अलग हजारों न्यूनतम मजदूरी दरें थीं। आस-पड़ोस के जिलों के कामगारों तक को एक ही काम के लिए काफी अलग-अलग रकम मिलती थी। वेतन संहिता में मजदूरियों की एक समान परिभाषा के साथ राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्थापित की गई। इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि किसी को भी एक गरिमापूर्ण न्यूनतम सीमा से नीचे मजदूरी नहीं मिले तथा समान कार्य के लिए एक बराबर मजदूरी सिर्फ आडंबर नहीं, बल्कि नियम बन जाए। इससे श्रम के एक से दूसरे स्थान पर गमन में भी मदद मिलती है। इस संहिता ने सुनिश्चित किया कि एक से दूसरे राज्य में जाने वाले मजदूर के वेतन के अधिकार भी उसके साथ चलें।

औद्योगिक संबंध संहिता लचीलेपन और निष्पक्षता के बीच एक समान संतुलन बनाती है। भारत की अर्थव्यवस्था अब विनिर्माण, सेवाओं और तेज़ी से बढ़ते गिग क्षेत्र का मिश्रण है। लॉजिस्टिक्स, खुदरा और निर्माण जैसे कई उद्योग मौसमी माँग और परियोजना-आधारित कार्य के साथ संचालित होते हैं। निश्चित अवधि के अनुबंध अब वैध और मानकीकृत हो गए हैं। अब कंपनियां वेतन या लाभ की समानता से समझौता किए बिना नियुक्ति कर सकती हैं।

भारत की स्थिरता की विशिष्ट स्थिति क्या दर्शाती है?

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . एक दूर दृष्टि वाला अर्थशास्त्री नई दिल्ली में खड़ा होकर चारों ओर की अशांति को देख-समझ सकता है। इस साल की शुरुआत में भारत के पूर्वोत्तर पड़ोसी देश नेपाल में असमानता को लेकर "जेन-जी" के आंदोलन से विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। इसका मुख्य कारण था कि जहां एक और आम नेपाली नागरिक बेरोजगारी से जूझ रहा था वहीं दूसरी ओर राजनीतिक राजवंशों के बच्चे इंस्टाग्राम पर विदेशों में बिताई गई अपनी शानदार छुट्टियों और डिजाइनर कपड़ों का प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले बांग्लादेश के छात्रों ने भी पिछले साल शेख हसीना की सरकार को हटाने के लिए क्रांति का नेतृत्व किया, जो 2009 से प्रधानमंत्री थीं।

भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश श्रीलंका में लोगों ने 2022 में राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। श्री राजपक्षे के कार्यकाल में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण देश दिवालिया हो गया था तथा ईंधन और दवाइयों का संकट हो गया था। देश के पश्चिम में स्थित पाकिस्तान को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है तथा आईएमएफ द्वारा भी उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया गया है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। इस वर्ष देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ वार का सामना कर रहा है। भारत को रूस से तेल की खरीद के कारण विशेष रूप से इस दंडात्मक टैरिफ का निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही इस वर्ष भारत ने परमाणु-सशस्त्र पाकिस्तान के साथ भी युद्ध का सामना किया था। देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी आईएमएफ के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इस बीच, भारत की दस वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड दर वर्ष की शुरुआत से 7 प्रतिशत से थोड़ा कम है तथा पाकिस्तान और श्रीलंका को जो 12 प्रतिशत ब्याज दर देनी पड़ रही है यह उससे काफी कम है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 700 अरब डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 18 प्रतिशत है—जो 11 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। विकास दर 6 से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। भारत हमेशा कभी इतना स्थिर नहीं रहा जितना आज है।

प्रवर्तन से सुविधा तक : व्यवसाय से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था और श्रम कल्याण के लिए वेतन संहिता, 2019 के आशय

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में, जहाँ न्यायसंगत वेतन, सम्मानजनक कार्य और श्रमिक संरक्षण टिकाऊ विकास के मूल तत्व हैं, वेतन संहिता, 2019 भारत के लिए प्रवर्तन से सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करती है। वियतनाम जैसे अनेक विकासशील देशों के उदाहरण दर्शाते हैं कि समयबद्ध और सुविचारित श्रम सुधार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करते हुए आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं। वियतनाम में न्यूनतम वेतन सुधार और श्रमिकों की सुरक्षा के संवर्धित उपायों सहित श्रम कानूनों के किए गए बदलावों की बदौलत विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और औपचारिक रोजगार में निरंतर वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि न्यायसंगत वेतन प्रथाओं को सुनिश्चित करना विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, सम्मानजनक कार्य और समावेशी आर्थिक विकास से संबंधित लक्ष्यों सहित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए आवश्यक है । साथ ही, दुनिया भर के व्यवसायों ने अत्यधिक नियामक बोझ, जटिल अनुपालन संरचनाओं, और दंडात्मक प्रवर्तन के बारे में चिंता भी व्यक्त की है, जो तेजी से बदलते वैश्विक बाजार में उनकी प्रगति और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

ओम प्रकाश गुप्ता
(अखिल भारतीय महासचिव, लघु उद्योग भारती द्वारा)

दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने और वैश्विक श्रम बाजार में अहम प्रतिभागी होने नाते भारत इन चुनौतियों से अछूता नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत विशाल कार्यबल (53.53 करोड़) के साथ (आर्थिक समीक्षा, 2021-22), देश ने लंबे समय तक श्रमिकों के लिए वेतन में बराबरी सुनिश्चित करने और नियोक्ता,ओं के लिए अनुपालन के ढाँचे को आसान बनाने की दोहरी चुनौती का सामना किया है।

वेतन से जुड़े अनेक कानूनों (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; न्यू नतम वेतन अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; और समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976) और उनके ओवरलैपिंग प्रावधानों तथा उन्हें लागू करने में आने वाली मुश्किलों की वजह से अक्सर नियोक्तापओं के लिए भ्रम, दोहराव और अनुपालन की चुनौतियाँ उत्पकन्न होती थीं। इन कमियों ने आर्थिक उत्पादकता और श्रमिकों के कल्याण दोनों में बाधा उत्पनन्न की। वेतन संहिता, 2019 इन चारों मौजूदा कानूनों को एक ही सुव्यवस्थित ढाँचे में समेकित कर इन समस्याओं को हल करती है। यह सरलीकरण वेतन मानकों की एक जैसी परिभाषाएँ और लगातार अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे गैर-ज़रूरी ओवरलैप खत्म होते हैं और नियोक्ता ओं के लिए अनुपालन आसान हो जाता है, साथ ही श्रमिकों को समय पर और न्यायिसंगत वेतन की गारंटी मिलती है। यह संहिता प्रशासनिक जटिलता को कम करके, पारदर्शिता, दक्षता और नियोक्तास-कर्मचारी संबंधों में बेहतरी को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है। इस तरह, वेतन संहिता, भारत का अपनी श्रम नीतियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास है। जो यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों की सुरक्षा और व्यावसायिक दक्षता दोनों का एक-दूसरे को मज़बूत करते हुए साथ-साथ आगे बढ़े। वेतन की एकसमान **परिभाषा :** वेतन संहिता, 2019 के तहत लाया गया एक मुख्य सुधार "वेतन" की एक समान और पूरी परिभाषा को अपनाया जाना है, जो पहले के विभाजित दृष्टिकोण की जगह लेता है, जिसमें हर श्रम कानून की अपनी अलग परिभाषा थी। इस असंगतता के कारण नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए अक्सर भ्रम, मुकदमेबाजी और अनुपालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न होती थीं, क्योंकि एक ही शब्द "वेतन" विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग अर्थ रखता था। परिभाषा को मानकीकृत करके, वेतन संहिता वेतन गणना में ज़्यादा पारदर्शिता और प्रशासनिक सरलता लाएगी। अब यह एकसमान परिभाषा स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि "वेतन" में क्या-क्याय शामिल होगा, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता शामिल हैं, जबकि बोनस, गृह किराया भत्ता और ओवरटाइम भुगतान जैसे खास घटकों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा : जीएसटी से जुड़े सुधार भारत की स्वास्थ्य गाथा को नए सिरे से लिख रहे हैं

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

56वीं जीएसटी परिषद का निर्णय प्रत्येक भारतीय को किफायती तरीके से गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ नीतिगत निर्णय व्यवस्थाओं में बदलाव लाते हैं और कुछ ऐसे दुर्लभ सुधार भी होते हैं, जिनमें जिंदगी को नया रूप देने की ताकत होती है। 56वीं जीएसटी परिषद द्वारा किए गए व्यापक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर संबंधी सुधार निर्णायक रूप से बाद वाली श्रेणी में आते हैं। चार दशकों से भी अधिक समय में भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को विकसित होते देखने वाले एक व्यक्ति के रूप में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह एक क्रांतिकारी बदलाव है।

शासन और करुणा का मेल

जरा भारत के श्रेणी-2 वाले एक शहर में एक ऐसी मां की कल्पना कीजिए, जो अपने बच्चे को एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से जूझते हुए देख रही है। हाल ही तक, इलाज की भारी लागत के कारण उसके सामने असंभव विकल्प थे - अपना घर बेच दो, भारी ब्याज दरों पर उधार लो या फिर असहाय होकर देखते रहो। सरकार द्वारा 36 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त करने के फैसले ने इस क्रूर गणित को पूरी तरह से बदल दिया है और उस मां के चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

ये कोई क्रमिक तरीके से धीरे- धीरे होने वाले बदलाव नहीं हैं। कैंसर की चिकित्सा, हृदय रोग संबंधी दवाएं, आनुवंशिक रोगों एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार - ये सभी अब जीएसटी से पूरी तरह मुक्त हैं। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, जिसमें 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, को साथ मिलाकर हम दुर्लभ रोगों से प्रभावित 7.2 करोड़ भारतीयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक मानवीय चेहरे वाले शासन का उदाहरण है।

उम्मीद का गणित

आंकड़े अक्सर इंसानी कहानियों को धुंधला कर देते हैं। लेकिन इस मामले में, वे ऐसी कहानियों को स्पष्ट करते हैं। जरा गौर कीजिए कि व्यवहार में इन सुधारों के मायने क्या हैं: आनुवंशिक कोलेस्ट्रॉल संबंधी विकार से जूझ रहे एक मरीज को सालाना लगभग 48,000 रुपये की बचत हो सकती है। गुर्दे, हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली एक दुर्लभ बीमारी, फैब्री रोग से जूझ रहे मरीज के इलाज की लागत में सालाना 19 लाख रुपये तक की कमी आ सकती है। यहां तक कि बेहद आम पायी जाने वाली पुरानी बीमारियों के लिए भी, यह राहत काफी बड़ी है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों को सालाना 6,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

ये बचत न सिर्फ बजट पर पड़ने वाले दबाव को कम करती हैं, बल्कि इनकी वजह से जानें भी बचती हैं। बचाया गया हर एक रुपया इलाज की निरंतरता

प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्र
(नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मानद प्रोफेसर)

सुनिश्चित करता है, परिवारों को चिकित्सा की वजह से छाने वाली कंगाली से बचाता है और मरीजों को बीमारी से लड़ने के क्रम में सम्मान एवं सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।

दवाओं से परे

इन सुधारों की खूबी उनके व्यापक प्रभाव में निहित है। आवश्यक दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत, चिकित्सा उपकरणों पर 18 प्रतिशत/12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और नैदानिक उपकरणों पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करके, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दिया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर दिया जाने वाला पूर्ण छूट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह कदम इस तथ्य को स्वीकार करता है कि वित्तीय सुरक्षा भी उपचार जितनी ही महत्वपूर्ण है। इस कदम का आशय सिर्फ आज स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने से नहीं है; बल्कि इसका संबंध भविष्य में भी इस किफायती सेवा को स्थायी बनाने से है। आवश्यक और जटिल जेनेरिक दवाओं के स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहित करके, ये सुधार 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना को साकार करते हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भारत आयात पर निर्भरता का बंधक न बने। एक सरलीकृत कर संरचना का अर्थ यह है कि दवा कंपनियां अनुपालन संबंधी कसरतों के बजाय नवाचार एवं गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित कर सकती हैं।

सर्वव्यापी प्रभाव

मेरी नजर में सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात यह है कि: ये सुधार सकारात्मक चक्र बनाते हैं। कम लागत का मतलब है उपचार संबंधी बेहतर अनुपालन। इस बेहतर अनुपालन का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी बेहतर नतीजे। बेहतर नतीजों का मतलब है स्वास्थ्य सेवा पर पड़ने वाले बोझ में दीर्घकालिक स्तर पर कमी। किफायती निवारक देखभाल का मतलब है शीघ्र उपाय। शीघ्र उपाय का मतलब है रोग का बेहतर निदान और समग्र लागत में कमी। एकाएक, दिहाड़ी मजदूर को दवा और भोजन के बीच चुनाव नहीं करना पड़ेगा। एक मध्यमवर्गीय परिवार को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति के लिए अपनी बचत खर्च नहीं करनी पड़ेगी। बुज़ुर्गों को इलाज के खर्चों के लिए पूरी तरह बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य बीमा अब एक आकांक्षा के बजाय सुलभ हो गई है।

विकसित भारत का एक खाका

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। इस संदर्भ में, यह सुधार एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है: स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास एक खोखली प्रगति है। 56वीं जीएसटी परिषद ने यह माना है कि 'विकसित भारत' के लिए सबसे पहले एक स्वस्थ भारत होना जरूरी है - एक ऐसा भारत जहां चिकित्सा संबंधी निदान वित्तीय संकट का कारण न बने; एक ऐसा भारत जहां उपचार भुगतान की क्षमता के बजाय नैदानिक जरूरतों के आधार पर निर्धारित हो। परिवर्तनकारी शासन कुछ ऐसा ही होता है - छिटपुट बदलाव नहीं, बल्कि बुनियादी बातों की पुनर्कल्पना। इसका मतलब यह समझना है कि स्वास्थ्य सेवा कोई कर लगाने लायक विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि नागरिकों को सक्षम बनाने संबंधी एक बुनियादी जरूरत है।

आगे की राह

बेशक, अकेले कर संबंधी सुधार भारत की स्वास्थ्य सेवा संबंधी सभी चुनौतियों का समाधान नहीं कर पायेंगे। हमें अभी भी अधिक संख्या में डॉक्टरों, बेहतर बुनियादी ढांचे, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, निरंतर दवाओं से जुड़े नवाचार और रचनात्मक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि: इन जीएसटी सुधारों ने उल्लेखनीय बदलाव लाया है। इन्होंने यह साबित कर दिया है कि जब नीतियां सहानुभूति एवं दूरदर्शिता के साथ बनाई जाती हैं, तो वास्तविक बदलाव संभव होता है। जैसे-जैसे इन सुधारों के बाद के बिक्री के आंकड़े और मामले (केस स्टडीज) सामने आ रहे हैं, उन बातों की निरंतर पुष्टि हो रही है जो हमेशा से नैतिक रूप से स्पष्ट थीं: सुलभ स्वास्थ्य सेवा मात्र अच्छी नैतिकता का नहीं, बल्कि अच्छी अर्थव्यवस्था का परिचायक है। स्वस्थ नागरिक उत्पादक नागरिक साबित होते हैं। सुरक्षित परिवार स्थिर परिवार साबित होते हैं। बीमाकृत आबादी आत्मविश्वास से लबरेज आबादी होती है। 56वीं जीएसटी परिषद ने भारत को कर राहत से कहीं ज्यादा कुछ दिया है। इसने लाखों परिवारों को कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज दी है: उम्मीद। यह उम्मीद कि बीमारी का मतलब कंगाली नहीं है। यह उम्मीद कि इलाज संभव है। यह उम्मीद कि आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा स्वस्थ होगा। विकसित भारत की यात्रा की कहानी में, इस सुधार को एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर याद किया जाएगा - एक ऐसा क्षण जब स्वास्थ्य सेवा ने वास्तव में विशेषाधिकार से अधिकार, आकांक्षा से हकीकत बनने की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। यह सिर्फ एक अच्छी नीति ही नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी नेतृत्व है।

गुरू नानक स्टेडियम में लाइट एंड साउंड शो आज

● गुरू साहिब के जीवन, दर्शन और शहादत पर डालेगा प्रकाश ● डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल द्वारा लोगों से परिवार सहित आने की अपील

• **जालंधर ब्रीज.** कपूरथला

श्री गुरू तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित गुरू साहिब के जीवन, दर्शन और शहादत पर आधारित लाइट एंड साउंड शो कल 14 नवंबर को गुरू नानक स्टेडियम में शाम 5 बजे से शुरू होगा।

डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरू तेग बहादर जी की शहीदी शताब्दी से संबंधित आयोजित समारोहों की श्रृंखला के तहत पूरे पंजाब में लोगों को गुरू साहिब की जीवनी से अवगत कराने के उद्देश्य से लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जा रहे है। उन्होंने जिला वासियों से परिवार सहित गुरू नानक स्टेडियम पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लोगों की सुरक्षा, सुचारू यातायात, पार्किंग, पीने का पानी, मेडिकल सुविधा आदि के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो के लिए कोई एंट्री फीस या पास की आवश्यकता नहीं है। संगत के लिए प्रवेश खुला है। इस मौके पर एसएसपी गौरव तूरा ने कहा कि कपूरथला पुलिस द्वारा संगत के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवनीत कौर बल्ल, एसडीएम इरविन कौर तथा अन्य विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

• डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल एवं एसएसपी गौरव तूरा गुरू नानक स्टेडियम कपूरथला में लाइट एंड साउंड शो की तैयारी का जायजा लेते हुए।

अब तक 11 लाख से अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिला

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने में कोई कसर न छोड़ते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब सरकार की सक्रिय पहल के चलते 12 नवंबर तक 11,31,270 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ प्राप्त हुआ है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया जोर-शोर से जारी है। अब तक 96,920 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने के साथ पटियाला जिला राज्य में सबसे आगे है।

उल्लेखनीय है कि 12 नवंबर की शाम तक राज्यभर की मंडियों में कुल 1,54,78,162.41 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है। इनमें से 1,53,89,039.51 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कुल फसल का 99 प्रतिशत है। कुल उठान का आंकड़ा 1,41,09,483.18 मीट्रिक टन है, जो अब तक खरीदी गई फसल का 91 प्रतिशत बनता है।

टांडा की चंडीगढ़ कालोनी में नशा तस्कर के अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा

स्थानीय निवासियों ने पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

पंजाब सरकार की ओर से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू किए गए 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के अंतर्गत नशे के खात्मे और नशा तस्कर की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए होशियारपुर व टांडा पुलिस ने संयुक्त अभियान के अंतर्गत टांडा की चंडीगढ़ कालोनी में हुए एक अनधिकृत निर्माण को आज ढहा दिया। यह अवैध निर्माण कमलेश पत्नी जीवन लाला निवासी वार्ड नंबर 11, चंडीगढ़ कालोनी की ओर से किया गया था। एसपी (पीबीआई) मेजर सिंह ने बताया कि एस.एस.पी. होशियारपुर संदीप कुमार मलिक के निर्देशानुसार सिविल प्रशासन की उपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कमलेश रानी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत कुल 16 मामले दर्ज है और इस समय यह तस्कर जेल में बंद है।

उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार के निर्देशों पर होशियारपुर पुलिस की ओर से नशे और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नशा तस्करों को चेतावनी दी कि या तो नशा तस्करी छोड़कर कोई और काम कर लें, या सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

उन्होंने बताया कि इन तस्करों से स्थानीय लोग बहुत परेशान थे, जिसके लिए उन्होंने पंजाब सरकार की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों ने कहा कि वे पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में नशे को खत्म करने के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का स्वागत करते हैं।

• 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के अंतर्गत टांडा की चंडीगढ़ कालोनी में नशा तस्कर के अनधिकृत निर्माण को ढहाए जाने का दृश्य।

थल सेना भर्ती अभियान में शानदार योगदान के लिए भारती शर्मा को किया सम्मानित

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो जालंधर की करियर काउंसलर भारती शर्मा को थल सेना भर्ती रैली तथा स्थानीय युवाओं को आगामी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025-26 की तैयारी के लिए प्रेरित करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया। प्रशंसा पत्र सौंपते हुए डा. अग्रवाल ने भारतीय सेना भर्ती दफ्तर जालंधर के सहयोग से वर्ष 2025-26 के भर्ती सेशन में भारती शर्मा द्वारा अथक एवं समर्पित भावना से की गई मेहनत की सराहना की।

उन्होंने कहा कि भारती शर्मा के निरंतर प्रयासों और व्यावसायिक नेतृत्व के कारण हाल ही में हुई भर्ती रैली में पिछले वर्षों की तुलना में युवाओं का पंजीकरण दोगुना से भी अधिक हो गया।

उन्होंने निःशुल्क कोचिंग तथा काउंसलिंग सत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका की भी प्रशंसा की।

डा.अग्रवाल ने भारती शर्मा द्वारा किए गए अथक प्रयासों, सुचारु योजना और पेशेवर नेतृत्व को मिसाली करार देते हुए कहा कि इनके प्रयास सिविल एवं सैन्य सहयोग के उच्चतम मानकों को दर्शाते है।

पंजाब सरकार ने ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए जारी किया 332 करोड़ का ऐतिहासिक फंड : हरपाल सिंह चीमा

कहा- अगली किश्त दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को तेज करने, आवश्यक सेवाओं को बेहतर बनाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण किश्त जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इसी श्रृंखला में 334 करोड़ रुपये की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी, ताकि ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह बना रहे।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से ही विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत यह राशि

ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों, जैसे कि सैनिटेशन बॉक्स की स्थापना आदि के लिए उपयोग की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 332 करोड़ रुपये की राशि को रणनीतिक रूप से टाइड और अनटाइड फंडों में विभाजित किया गया है ताकि सामान्य स्थानीय विकास और विशेष स्वच्छता कार्य दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने बताया कि 156 करोड़ रुपये की ग्रांट अनटाइड फंड के रूप में दी जा रही है, जिसे ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में उपयोग कर सकती हैं। वहीं 176 करोड़ रुपये की राशि टाइड फंड के रूप में स्वच्छता कार्यों के लिए निर्धारित की गई है। यह संपूर्ण ग्रांट ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बीच 70:20:10 के अनुपात में वितरित की जाएगी।

जिला-वार वितरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 22 जिलों में कुल 3,329,750,900 रुपये (जिसमें 1,766,319,970 रुपये टाइड फंड और 1,563,430,930 रुपये अनटाइड फंड शामिल हैं) आवंटित किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक राशि वाले जिले लुधियाना (टाइड 200,143,127 रुपए , अनटाइड 133,905,292 रुपए), होशियारपुर (टाइड 170,847,451 रुपए, अनटाइड 114305, 089 रूपये और गुरदासपुर (टाइड 165563,924 रुपए, अनटाइड 110770,166 रुपए) हैं। अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोज़पुर, फाज़िल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं।

एडीसी ने राजस्व अधिकारियों के साथ की बैठक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी रिकवरी की समीक्षा की

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर ने आज अलग-अलग विभागों के साथ बैठक कर उनकी ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों, योजनाओं और लंबित कार्यों की गहन समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में ईजी रजिस्ट्रेशन और मुकेरियां तहसील कांप्लेक्स के नवीनीकरण संबंधी प्रगति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही 'मेरा घर मेरे नाम' स्कीम की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली गई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी रिकवरी का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने लंबित भूमि राजस्व बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के चल रहे मामलों की स्थिति रिपोर्ट, खसरा-वाइज मैपिंग, मुसावी- कैडस्ट्रल डिजिटाइजेशन, जमाबंदी, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा ईजी जमाबंदी सेवाओं (ऑनलाइन सेवाएं, म्यूटेशन, रपट, फर्द बदर, बैंक लॉगिन आईडी बनाने आदि) की समीक्षा की गई।

मादा भ्रूण हत्या जैसी बुराई को मिटाने के लिए हर वर्ग को देना चाहिए सहयोग : सिविल सर्जन

बैठक में दोनों स्कैन सेंटरों की रिन्यूअल अर्ज़ियों को दी गई मंजूरी

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

सिविल सर्जन कार्यालय में हुई जिला पीसी-पीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक जिले में पीसी-पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, गुरुवार को जिला सलाहकार समिति (पी.सी.-पी.एन.डी.टी.) की बैठक का आयोजन सिविल सर्जन जालंधर डॉ. राजेश गर्ग की अध्यक्षता में सिविल सर्जन कार्यालय में किया गया।

बैठक के दौरान सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नए स्कैन सेंटर द्वारा नई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे थे। जिला सलाहकार समिति के सदस्यों की सहमति से इस स्कैन सेंटर को मंज़ूरी दे दी गई। इसके साथ ही दो स्कैन सेंटरों ने अपनी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए आवेदन किए थे। बैठक में समिति के सदस्यों की सहमति से दोनों स्कैन सेंटरों की रिन्यूअल अर्ज़ियों को मंज़ूरी दी गई।

सिविल सर्जन ने कहा कि जिले में पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कैनिंग सेंटर्स की नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मादा भ्रूण हत्या एक सामाजिक बुराई है, इसे खत्म करने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर सहयोग देना चाहिए। डॉ. गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रूण के लिंग की जांच करवाना या करना गैरकानूनी है, और इस अपराध में शामिल दोषियों के खिलाफ पी.सी.-पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. रमन गुप्ता, डॉ. वरिंदर कौर थिंद (एस.एम.ओ., गायनी विभाग, सिविल अस्पताल जालंधर), गगनदीप (सहायक जिला अटॉर्नी जालंधर), सोशल एक्टिविस्ट परवीन अबरोल, लीगल प्रोबेशन अधिकारी संदीप भाटिया, डिप्टी एम.ई.आई.ओ. असीम शर्मा और जिला पी.एन.डी.टी. कोऑर्डिनेटर दीपक बपौरिया उपस्थित थे।

रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक बंद रखने का आदेश

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, फोटो/वीडियो क्लिप अपलोड करने पर पाबंदी

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगहों पर रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने की चीज़ों आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। आदेशों में सभी जगह को 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित शोर के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा या उनकी मात्रा कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न कोई भी शोर उसकी सीमा के बाहर नहीं सुना जाएगा। संगीत प्रणाली वाले वाहनों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संगीत प्रणाली द्वारा उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यह आदेश 07-01-2026 तक लागू रहेगा। पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम नंबर 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर, मैरिज पैलेस/होटल/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर और अन्य सभा स्थलों पर हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, हिंसा/झगड़े व हथियारों का महिमामंडन करने वाले फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह आदेश 06.01.2026 तक लागू रहेगा।

अंबेडकर भवन में पेंशनभोगियों के कल्याण शिविर का आयोजन

जालंधर (जालंधर ब्रीज). भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के तहत पंजाब टेलीकॉम सर्कल, चंडीगढ़ के कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (सीसीए) के पंजाब राज्य में फील्ड ऑफिस ने 13.11.2025 को जालंधर में अंबेडकर भवन में पेंशनभोगियों के कल्याण शिविर का आयोजन किया। "नेशन-वाईड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0, नव., 1-30, 2025" के हिस्से के रूप में, यह शिविर पेंशनभोगियों की भलाई और सुविधा के लिए समर्पित था। इस शिविर का उद्देश्य जीवन प्रमाण पत्र के अद्यतन की सुविधा प्रदान करना, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना और पेंशनभोगियों के बीच साइबर सुरक्षा और बैंकिंग से संबंधित मुद्दों की समझ को बढ़ाना था। शिविर का उद्घाटन और अध्यक्षता डॉ. मनदीप सिंह, जॉइंट कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स (जॉइंट सीसीए), पंजाब ने की, साथ ही श्री आर.एल. जाखू, प्रिंसिपल सीसीए (सेवानिवृत्त) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

जब भी मुश्किल पल आए हमने उनका बाखूबी सामना किया : शुभमन गिल

दक्षिण अफ्रीक के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज आज से शुरू

स्पोर्ट्स डेस्क. टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के महत्व पर ज़ोर दिया, जो शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शुरू होगी। गिल ने मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को एक मज़बूत प्रतिद्वंद्वी बताया और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का ज़िक्र किया। गिल ने कठिन परिस्थितियों से निपटने की अपनी टीम की क्षमता पर भरोसा जताया और एक अच्छे मैच की उम्मीद जताई। शुभमन गिल ने कहा कि मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीसी फ़ाइनल खेलने के लिए ये दो टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है। वे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चैंपियन हैं। गिल ने कोलकाता टेस्ट से पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए आसान नहीं होगा। मुश्किल पल भी आएंगे। लेकिन एक टीम के तौर पर हमने दिखाया है कि जब भी मुश्किल पल आए हमने उनका बाखूबी सामना किया है। और जहाँ तक विकेट की बात है, मुझे लगता है कि यह एक विशिष्ट भारतीय विकेट है। यह एक अच्छा विकेट लग रहा है और उम्मीद है कि यह एक अच्छा मैच होगा।

फोटो-बीसीसीआई

गिल ने एशिया में दक्षिण अफ्रीका के हालिया प्रदर्शन की भी प्रशंसा की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वापसी और गेंदबाजों के अनुकूल पिचों पर भी बड़े स्कोर बनाने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चैंपियन के रूप में उनकी स्थिति को स्वीकार किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि लगातार बड़े स्कोर (350-400) बनाना मैच पर नियंत्रण बनाए रखने की कुंजी है।

गिल ने आगे कहा कि लेकिन मेरा मतलब है कि अगर आप उनकी टीम को देखें, तो बल्लेबाज नियमित रूप से 300 रन बना रहे हैं और विकेट गेंदबाजों के लिए मददगार है। अगर आप नियमित रूप से 300, 350 रन बनाते रहेंगे, तो आपकी टीम हमेशा मैच में रहेगी। इसलिए एक टीम के तौर पर हम भी यही देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम 350, 400 रन बना पाते हैं, तो आप हमेशा बेहतर स्थिति में रहेंगे।

आम आदमी क्लीनिकों के लिए मेडिकल अधिकारियों का साक्षात्कार सम्पन्न

जालंधर (जालंधर ब्रीज). आम आदमी क्लीनिकों के लिए मेडिकल अधिकारियों के साक्षात्कार गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय, जालंधर में संपन्न हुए। इन साक्षात्कारों का संचालन सिविल सर्जन जालंधर डॉ. राजेश गर्ग की अध्यक्षता में पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया। इंटरव्यू के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में सहायक सिविल सर्जन डॉ. जोति फुकेला, जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. रमन गुप्ता शामिल थे।

सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग ने बताया कि आम आदमी क्लीनिकों के मेडिकल अधिकारियों की रिक्तियों के लिए मेरिट सूची तैयार करने के उद्देश्य से यह साक्षात्कार प्रक्रिया आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्त टीमों ने काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की जांच की और पूरी प्रक्रिया सुगमता एवं निष्पक्षता से संपन्न हुई। डॉ. गर्ग ने कहा कि पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम आदमी क्लीनिकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को निरंतर बेहतर बनाया जा रहा है। अब इन क्लीनिकों में टीकाकरण, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग व इलाज, तथा कुपोषित बच्चों की शीघ्र पहचान और उपचार जैसी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.